रोज़गार आंकड़े बोलते हैं... सरकारी क्षेत्र में बढ़ रही ठेकेदारी प्रथा

आमतौर पर यह धारणा प्रचलित है कि अधिकांश अनियंत्रित व अस्थायी नौकरियां निजी क्षेत्र में होती है लेकिन वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल अलग है। समूचें औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा सरकारी क्षेत्र में है। लेकिन इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में अस्थायी रोज़गार की निरपेक्ष संख्या भी बहुत बड़ी है, हालांकि सरकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की तुलना में हिस्सा छोटा है। निजी क्षेत्र के औपचारिक क्षेत्र में 1.5 करोड़ से ज़्यादा अस्थायी रोजगार है।

'स्टाफ़िग फेडरेशन' की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी रोज़गार में कम से कम 44 प्रतिशत लोग अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। इन मज़दूरों को कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलना तो दूर की बात है, इनमें से कईयों को न्यूनतम मज़दूरी भी नहीं मिलती। सरकारी कार्यशक्ति लगातार कम होती जा रही है और इसी के साथ स्थायी मज़दूरों की संख्या घटती जा रही है।

देश के औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग़ों की संख्या 4 करोड़ 97 लाख है। इनमें से 2 करोड़ 78 लाख लोग जीविका के लिए सरकार पर निर्भर करते हैं। इन सरकारी क्षेत्र के मज़दूरों में एक करोड़ 23 लाख लोग अस्थायी मज़दूर हैं। उक्त रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े 2013 के अंत के हैं। इन आकस्मिक मज़दूरों को काम या आमदनी की कोई सुरक्षा नहीं है। कम समय के लिए ठेके के मज़दूरों को मुख्यतया एकमुश्त मज़दूरी दे दी जाती है। उनको ई.पी.एफ़., ई.एस.आई., ग्रेच्युटी, नई पेंशन योजना इत्यादि की कोई सुविधा तक नहीं मिली हुई है।

जहां 1995 में औपचारिक क्षेत्र में कुल सरकारी मज़दूरों की संख्या एक करोड़ 94 लाख 70 हज़ार थी वहीं 2011 में यह घटकर एक करोड़ 75 लाख 50 हज़ार रह गयी। यानी इन 16 वर्षों में सरकारी संगठित क्षेत्र के मज़दूरों की संख्या में करीब 10 प्रतिशत गिरावट हो गयी। यह गिरावट केन्द्र सरकार के स्तर पर सबसे अधिक हुई है जहां कुल सरकारी क्षेत्र में रोज़गार की औसत सालाना गिरावट 0.65 प्रतिशत थी, वहीं केन्द्र सरकार के रोजगार में यह सालाना गिरावट 1.99 प्रतिशत की थी। यहां पर कुल सरकारी क्षेत्र में राज्यों और स्थानीय निकायों के कार्मिक शामिल हैं।

उक्त रिपोर्ट यह बताती है कि सरकारी कर्मचारियों में समूह-ग और समूह-घ (निचले स्तर के कर्मचारी) के कर्मचारियों में सबसे खराब असर हुआ है। इन दो समूहों में रोजगार में गिरावट 8.4 प्रतिशत दर्ज की गयी है। दूसरी तरफ़ समूह-क और समूह-ख में रोज़गारों की संख्या बढी है। 2001-02 और 2011-12 के बीच समूह-ख के रोजगारों में 27 प्रतिशत की वृद्धि और समूह-क के रोजगारों में 24.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले दशक में निचले स्तर के कर्मचारियों के कामों को बड़े पैमाने पर आउटसोर्स किया गया है।

सरकार द्वारा लागू की गयी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में काम करने वाले मज़दूरों की बड़ी तादाद लगी हुई है। इन बहुप्रचारित योजनाओं में काम करने वाले मज़दूरों को न तो पर्याप्त वेतन मिलता है और न ही पी.एफ. और ई. एस. आई. जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं। उक्त रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं तथा 9 लाख आशा कार्यकर्ता हैं। इन सभी को अवैतनिक कार्यकर्ता कहा जाता है और अधिकांश मामलों में इनको विभिन्न राज्यों में तय न्यूनतम मज़दूरी भी नहीं मिलती। इन कर्मियों को 1500 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाता है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सेंपल सर्वे आर्गनाइजेशन ने 2011-2012 का अनौपचारिक क्षेत्र और भारत में रोज़गार की स्थिति पर 68 वें चक्र का सर्वेक्षण जारी किया है। इस सर्वे के अनुसार, भारत में प्रत्येक 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति गैर कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। इन अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूरों में 80 प्रतिशत लोग बिना किसी लिखित संविदा के काम करते हैं और 72 प्रतिशत लोग़ों को कोई सामाजिक सुरक्षा सुविधा भी नहीं मिली हुई है। इनमें से 80 प्रतिशत मज़दूर किसी यूनियन या एसोसियेशन के सदस्य भी नहीं हैं। अनौपचारिक मज़दूरों को रोज़गार देने वाले मुख्य क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, थोक व खुदरा व्यापार, परिवहन और स्टोरेज हैं। अनौपचारिक मज़दूरों का सबसे अधिक हिस्सा पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है।

-नागरिक

राष्ट्र का सेवक

-प्रेमचंद

राष्ट्र के सेवक ने कहा-देश की मुक्ति का एक ही उपाय है और वह है नीचों के साथ भाईचारे का सलूक, पतितों के साथ बराबरी का बर्ताव। दुनिया में सभी भाई हैं, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं।

दुनिया ने जय-जयकार की। कितनी विशाल दृष्टि है, कितना भावुक हृदय।

उसकी सुन्दर लड़की इन्दिरा ने सुना और चिन्ता के सागर में डूब गयी। राष्ट्र के सेवक ने नीची जाति के नौजवान को गले लगाया।

दुनिया ने कहा-यह फ़रिश्ता है, पैगम्बर है, राष्ट्र की नैया का खेवैया है।

इन्दिरा ने देखा और उसका चेहरा चमकने लगा। राष्ट्र का सेवक नीची जाति के नौजवान को मन्दिर में ले गया, देवता के दर्शन कराये और कहा-हमारा देवता गरीबी में है, जिल्लत में है, पस्ती में है।

दुनिया ने कहा-कैसा शुद्ध अंत:करण का आदमी है! कैसा ज्ञानी!

इन्दिरा ने देखा और मुसकराई।

इन्दिरा राष्ट्र के सेवक के पास जाकर बोली-श्रद्धेय पिताजी, मैं मोहन से प्यार करना चाहती हूं।

राष्ट्र के सेवक ने प्यार की नज़रों से देखकर पूछा-मोहन कौन है?

इन्दिरा ने उत्साह भरे स्वर में कहा-मोहन वही नौजवान है, जिसे आपने गले लगाया, जिसे आप मन्दिर में ले गये, जो सच्चा बहादुर और नेक है। राष्ट्र के सेवक ने प्रलय की आंखों से उसकी ओर देखा और मुंह फेर लिया।

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा के 1-15 दिसम्बर को 2014 के अंक में समसामयिक मुद्दों पर अनेक विश्लेषणात्मक महत्वपूर्ण लेख पढने को मिले। ''हरियाणा बना बाबाओं का कुरूक्षेत्र 'स्वामी' रामदेव बनाम 'संत' राम रहीम'' तथा 'और कितने भस्मासुर' लेखों द्वारा रामदेव, राम रहीम व रामपाल बाबाओं के संदर्भ में सत्ता राजनीति व धर्म के गठजोड़ का पूरा पर्दाफ़ाश किया गया है।

गरीबी, बिमारी व उत्पीड़न से परेशान भोली-भाली जनता सुकून, शांति व राहत की तलाश में इन बाबाओं की शरण में जाती है और अंधविश्वास की शिकार बन जाती है। इसी अंधविश्वास के कारण ये तथाकथित स्वयंभू बाबा जनता को अपने मकड़जाल में फ़ांस लेते हैं जिससे जनता पर उनकी पकड़ मज़बूत हो जाती है। ये ढोंगी बाबा जनता को अपनी ढाल बनाकर अपने मंसूबे पूरे करते हैं। इनको सरकार, कानून व अदालत की कोई परवाह नहीं होती क्योंकि सरकार तो इनकी सहायता से ही बनती है। सतलोक आश्रम, बरवाला के रामपाल का किस्सा तो जग जाहिर हो चुका है। सिरसा स्थित सच्चा सौदा डेरा के राम रहीम पर डेरे की साध्वी से कथित यौन शोषण समेत डेरा अनुयायी रंजीत व पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले चल रहे हैं। इन मामलों में राम रहीम जमानत पर चल रहा हैं।

गौरतलब है कि बरवाला के रामपाल के शिष्यों की विडियों कॉन्फ्रेसिंग के ज़रिए रामपाल के बयान दर्ज करने की मांग तो अदालत ने रद्द कर दी थी, परंतु राम रहीम की उक्त तीनों मामलों में सी बी आई की अदालत में विडियो कॉन्फेसिंग के ज़रिए 6 दिसम्बर को सुनवाई हुई। इसके अतिरिक्त सेना की गुप्तचर एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सिरसा स्थित सच्चा सौदा डेरा में कुछ पूर्व सैनिक डेरे के अनुयायियों को सैनिक ट्रेनिंग दे रहे हैं।

केन्द्र में मोदी सरकार बनने के बाद उपेक्षित बाबा रामदेव ने जब उत्तराखंड की हरीश रावत की कांग्रेस सरकार से नज़दीकियां बढानी शुरू की तो भाजपा व संघ दोनों ही चौकन्ने हो गए और रामदेव को संतुष्ट करने में जुट गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पतंजलि पीठ, हरिद्वार जाकर रामदेव से मुलाकात कर उनकी काफ़ी प्रशंसा की। संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने तो संघ की राष्ट्रीय परिषद की बैठक पातंजलि पीठ में रखी जहां मोहन भागवत व रामदेव दोनों गले मिले और दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा की।

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के 'समाधिस्थ' प्रमुख आशुतोष महाराज का 15 दिन के भीतर अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। परंतु डेरा संस्थान के प्रबंधकों ने अदालत का फ़ैसला मानने की बजाए मुख्य सड़क से आश्रम तक जाने वाली सड़क पर बैरिकेड़ लगा दिए और भंडारे के नाम पर वहां लगभग 70000 भक्तों को इकट्ठा करने की योजना बना ली। इस पर वहां प्रतिदिन लगभग 500 भक्त इकट्ठा हो रहे हैं। यद्यपि आशुतोष महाराज को क्लीनिकली डैड घोषित किया जा चुका है और उनका पार्थिव शरीर डीप फ्रीज़र में रखा हुआ है। भक्तों को 'विश्वास' है कि उनके गुरूजी गहन समाधि में हैं और कभी भी समाधि से बाहर आ सकते हैं। अंधभक्तों की भीड़ प्रशासन के लिये कभी भी टकराव की स्थिति पैदा कर सकती है। स्पष्ट है कि इन सभी आश्रमों व तथाकथित बाबाओं को राजनीतिक दलों, सरकार व प्रशासन से आश्रय व संरक्षण मिलता है। विचारणीय प्रश्न है कि सत्ता राजनीति और धर्म का गठजोड़ देश को किस दिशा में लेकर जा रहा है।

'मोदी के तेज राज में ई एस आई मेडिकल कॉलेज की कछुआ गति', 'ई एस आई अस्पतालों में नियम विरुद्ध ठेकेदारी प्रथा', कामगारों का हित और उनकी सामाजिक सुरक्षा परम आवश्यक है तथा 'हर वर्ष 525 करोड़ बेवज़ह गंवाये जा रहे हैं-फ़टेहाल ई एस आई चिकित्सा सेवा के लिये हरियाणा सरकार कम दोषी नहीं' लेखों द्वारा स्पष्ट है कि चाहे यूपीए सरकार हो या एनडीए की मोदी सरकार दोनों का ही मज़दूरों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। मज़दूरों के वेतन से ई एस आई के नाम से पैसा काटकर भी उनको बिमारी के इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती।

जुलाई 2014 में ई एस आई कॉरपोरेशन ने सभी राज्य सरकारों को लिखा था कि उनके राज्य में बन रहे ई एस आई मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकारें अपने अंडर में ले ले। परंतु कार्पोरेशन की मीटिंग में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा इस फ़ैसले का कड़ा विरोध करने पर इस पर रोक लगाने का निर्णय किया गया। परंतु यक्ष प्रश्न है कि ई एस आई मेडिकल कॉलेज कब बनेगा और मज़दूरों की गाढी कमाई से कटा हुआ पैसा कब तक बेकार पड़ा रहेगा या बरबाद होता रहेगा और मज़दूरों को प्राइवेट अस्पतालों/सरकारी अस्पतालों के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ेगा तथा मज़दूरों के इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल सरकार से धन वसूल कर फलते-फूलते रहेंगे।

'किस मुंह से कहोगे वाड्रा को चोर-जन का धन, अदानी का फ़न, मोदी का जतन' तथा ' बाखबर बेंक लूट' आस्ट्रेलिया की कोयला खदानों का ठेका व एस बी आई के चेयरपर्सन द्वारा वहीं अदानी को 6000 करोड़ रुपयों का कर्ज देने में मोदी की कथित भूमिका व एन पीए का बैंकों से दिए गए कुल कर्ज़ के अनुपात का उचित विश्लेषण किया गया है। बैंकों के बढते एन पीए के लिए सरकार, प्रशासन व बैंक तीनों ही उत्तरदायी हैं। एनपीए को वसूल करने में बैंक लाचार व बेबस साबित हो रहे हैं और सरकार इस संबंध में भाषण देने के अलावा कोई ठोस कदम उठाने में बेबस दिख रही है। यह एक सामान्य सी बात है कि यदि किसी व्यक्ति ने बैंक से कर्ज़ ले रखा है तो बकाया कर्ज़ चुकता किए बिना उसे बैंक से और कर्ज़ नहीं मिल सकता। परंतु आश्चर्य है कि अदानी पर एस बी आई का 4800 करोड़ रुपये का कर्ज़ पहले से ही खड़ा है फ़िर भी उसे और कर्ज़ कैसे मिल गया, स्पष्ट है प्रधानमंत्री मोदी की मेहरबानी से।

लेख 'राजनीति का अंधा युग' में केन्द्र में भाजपा के ज़रिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सत्ता पर काबिज़ होने तथा भाजपा के विरोध में पूर्व जनता दल को पुनर्जीवित करने के प्रयास का सांगोपांग वर्णन किया गया है। इस प्रयास का नतीज़ा भी कहीं जनता पार्टी व जनता दल जैसा न हो जाए। अन्य प्रकाशित लेख भी प्रेरणादायक व प्रशंसनीय है।

-प्रो. जुगल किशोर गुप्ता

साझे की खेती

हालॉकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था लेकिन फ़िर भी डरा दिये जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाता था। इससे पहले वह शेर, चीते, मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। जब उससे हाथी ने कहा कि अब वह साझे की खेती करे तो किसान ने उसको बताया कि साझे की खेती में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले वह खेती कर सकता नहीं। इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढाई और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से लाभ यह होगा कि जंगल के छोटे-मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली हो जायेगी। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी के साथ मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।

किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ने तैयार हो गये तो वह हाथी को खेत में बुला लाया। किसान चाहता था कि फ़सल आधी-आधी बांट ली जाय। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफ़ी बिगड़ा। हाथी ने कहा-अपने और पराये की बात मत करो। यह छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की है। हम दोनों उसके स्वामी हैं। आओ हम मिलकर गन्ने खाएं।

किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सुंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा। आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ-साथ आदमी भी हाथी के मुंह की तरफ़ खिंचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया।

हाथी ने कहा-देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इसी तरह हाथी और आदमी की साझा खेती की पैदावार बंट गयी।

-असगर वजाहत

तुर्की-ब-तुर्की

''मोदी सरकार परिवर्तन की नहीं यू टर्न की सरकार है''

(नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा चुनाव पूर्व पार्टी घोषणाओं के विपरीत पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकार की घोषित योजनाओं को लागू करने पर कांग्रेस द्वारा प्रकाशित आरोप पत्र)

हमारा कहना है:-

- हम तो चुनाव पूर्व से ही कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा में सिर्फ़ चेहरे का फ़र्क है, चाल और चरित्र का नहीं। दरअसल भाजपा सरकार यू टर्न नहीं कर रही-वह तो जरूरी टर्न कर रही है।
- कांग्रेसी सरकार की मुख्य आर्थिक नीतियां कार्पोरेट हितों के द्वारा संचालित होती थीं। अपने तूफ़ानी चुनाव प्रचार में भाजपा के नरेन्द्र मोदी ने भी अपने कार्पोरेट रूझान को कभी छुपाया तो नहीं। जैसे कांग्रेस ने कार्पोरेट पैसे से चुनाव लड़ा वैसे ही मोदी ने भी। लिहाजा, मोदी भी कार्पोरेट जगत के लिये वही करेंगे जो मनमोहन और सोनिया करते थे। इसमें यू टर्न कहां हुआ?
- देखा जाय तो मोदी ने कार्पोरेटों के मतलब की फ़ाइलें ज़्यादा तेज़ी से निकाली हैं। इस लिहाज़ से वे मनमोहन सरकार के दिखाये रास्ते पर ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं। हद से हद कांग्रेस को यह तकलीफ़ हो सकती है कि मोदी का यार अडानी सबसे बढ-चढ कर मलाई मार रहा है। खैर यह सब तो कांग्रेस राज में भी होता था जहां जिंदल जैसों को लूट की विशेष छूट मिला करती थी।
- रहे स्थापित घराने, जैसे अम्बानी और टाटा; तो उनकी जैसी दादागिरी मनमोहन राज में थी वैसी ही मोदी राज में भी कायम है। जैसे कांग्रेसी राज में काला धन बेलगाम पैदा हो रहा था वैसे ही मोदी राज में भी हो रहा है। टैक्सचोरी और हवाला रैकेट भी बदस्तूर पहले की तरह जारी हैं। तो यू टर्न कहां?